

यातायात सुधार एवं सड़क दुर्घनाओं की रोकथाम को लेकर जिला सड़क सुरक्षा समिति की हुई बैठक

सिविस-लेन सड़क पर पुरई बोगदा की बढ़ेगी ऊंचाई

हरिभूमि न्यूज ►►दुर्ग

जिले में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कलेक्टर सभाकक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल भी शामिल हुए।

बैठक के प्रारंभ में विगत बैठक के पालन प्रतिवेदन की विभागवार समीक्षा की गई। जिसमें अधिकारियों



ने कार्य पूर्ण होने, अद्यतन प्रगति एवं की गयी विभागीय कार्यवाहियों की जानकारी दी। साथ ही जिले की सड़कों में यातायात सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न सुझावों पर विचार-विमर्श कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए। कलेक्टर सिंह ने यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने

तथा सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रभावी उपाय अपनाने के निर्देश दिए।

उन्होंने दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार अधिकारियों को सौंप गए विभागीय कार्य, रिफ्लेक्टर, स्पीड ब्रेकर एवं स्ट्रीट लाइट लगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने एनएचआई, लोक निर्माण

विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, लोक निर्माण विभाग को दुर्घटनाजन्य स्थलों का निरीक्षण कर आवश्यक त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसके अलावा भिलाई इस्पात संयंत्र वाहनों के लिए, भारतमाला सड़क से जोड़ने, भारतमाला सड़क पर पुरई के पास बोगदा की हाइट बढ़ाने, भिलाई में केनाल रोड निर्माण तथा बारिश के पूर्व सभी अण्डरब्रिजों की सफाई एवं आवश्यक मरम्मत पर भी चर्चा की गई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

न्यू आदर्श नगर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे

हरिभूमि न्यूज ►►दुर्ग

न्यू आदर्श नगर में सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत सामने आई है। इसे लेकर जनदर्शन में शिकायत की गई। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन में डिप्टी कलेक्टर उत्तम ध्रुव भी उपस्थित थे। जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, सीसी रोड निर्माण, ऋण



पुस्तिका सुधार, आर्थिक सहायता राशि दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आज 124 आवेदन प्राप्त हुए। खुसीपार क्षेत्र के नागरिकों ने बताया कि देवार मोहल्ला क्षेत्र में लंबे समय से चिट्ठा, गांजा, शराब और कबाड़ जैसे अवैध कारोबार संचालित किए जा रहे हैं। इसी प्रकार वार्ड 53 न्यू आदर्श नगर, महाराजा चौक से

बोरसी रोड क्षेत्र के रहवासियों ने होटल द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण और मुख्य मार्ग को बाधित किए जाने की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि होटल के सामने वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग और सड़क पर पानी डालने से दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। इस पर कलेक्टर ने दुर्ग आयुक्त को निरीक्षण कर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। चरोदा स्थित मानसरोवर विद्यालय जंजगिरी द्वारा भीषण गर्मी के दौरान शासन के निर्देशों के विपरीत स्कूल संचालित किए जाने की शिकायत की। आवेदक ने बताया कि बच्चों को सुबह से दोपहर तक स्कूल बुलाकर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

ट्रांसफर शुल्क में बढ़ोतरी के विरोध कांग्रेस ने आरटीओ दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन



हरिभूमि न्यूज ►►दुर्ग

वाहनों की खरीदी-बिक्री और समान्य से रूप में नाम ट्रांसफर के शुल्क में बढ़ोत्तरी को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को आरटीओ दफ्तर के बाहर विरोध दर्ज करया।

बता दें कि शासन ने बड़े वाहनों के ट्रांसफर शुल्क को 1 हजार से बढ़ाकर 2500 और चार पहिया वाहन का शुल्क 600 से बढ़ाकर 1 हजार रुपए कर दिया है। इसके अलावा लगातार ई चालान के नाम

कार्रवाई की जा रही है। इसके विरोध में जिला कांग्रेस अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल के नेतृत्व में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आरटीओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। समस्याओं की निराकरण की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों कांग्रेसियों ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में जमकर नारेबाजी की करीब एक घंटा जमीन में बैठकर जमकर नारेबाजी करते रहे उसके

बाद परिवहन अधिकारी के आने के बाद उनको ज्ञापन सीपा गया। मोटरसाइकिल के नए रजिस्ट्रेशन का शुल्क 150 से बढ़ाकर 200, कार के नए रजिस्ट्रेशन का शुल्क 500, पुरानी मोटरसाइकिल के वेरिफिकेशन, मार्किंग शुल्क को

■ भारी वाहनों का शुल्क 1 हजार से बढ़ाकर 2500 और चार पहिया वाहनों का 600 से बढ़ाकर 1 हजार रुपए किया गया

100 से बढ़ाकर 300, पुरानी कार के मार्किंग शुल्क को 500, ट्रक के मार्किंग शुल्क को 1000, पुरानी मोटरसाइकिल के ट्रांसफर शुल्क को भी बढ़ाया गया है। इसका कांग्रेस ने विरोध किया। इस अवसर पर अलताफ अहमद, नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले, रायसिंह ढिकोला, नासिर खोखर, सुशील भारद्वाज, मनीष बघेल, आनंद कपूर ताम्रकार, गुरदीप सिंह भाटिया, दुष्यंत देवांगन सहित अन्य मौजूद थे।

खबर संक्षेप



भाजपा में घर बैठे नहीं चलेगी राजनीति

दुर्ग। भारतीय जनता पार्टी की आगामी कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन तथा जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने के उद्देश्य से बोरो लिटिया भाजपा मंडल की मासिक आत्मनिर्भर बैठक तुमाखुर्द में हुई। बैठक में मुख्य वक्ता जिला मंत्री गिरीशा साहू थे। अनुशासन की परंपरा को अनुरूप मंडल महामंत्री सूरज देशमुख ने सुमधुर संगठन गीत का सामूहिक गान कराया गया, जिसने उपस्थित समस्त कार्यकर्ताओं में राष्ट्रभक्ति, समर्पण और कार्यपरायणता के भाव का संचार किया। गिरीशा साहू ने कहा कि अब घर बैठे राजनीति नहीं होगी। प्रदेश, जिला एवं मंडल स्तर के प्रत्येक पदाधिकारी को जनता के बीच जाना होगा। सघन जनसंपर्क करना अनिवार्य है। बैठक में मंडल अध्यक्ष बीरबल पटेल, सूरज देशमुख, नीलांबर साहू, अरविंद पटेल, रामचंद्र साहू, सीताराम पटेल, गौरभभक्त पटेल, राजेश पटेल, हेमलाल निषाद, सुरेश उमरे सहित अन्य मौजूद थे।

अंतर्जातीय विवाह करने वाले 65 दंपतियों को मिले 1.62 करोड़ रुपए दुर्ग। छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति

विकास विभाग द्वारा छुआछूत निवारणार्थ संचालित अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत जिले के कुल 65 दंपतियों के लिए 1.62 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास से मिली जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र दंपति को कुल 2.50 लाख की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस राशि में से 1 लाख सीधे हितग्राही के खाते में हस्तांतरित कर दिए जाते हैं, जबकि शेष 1.50 लाख की राशि को तीन वर्ष के लिए संयुक्त सावधि जमा (फिक्स डिपोजिट) के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। दंपति के तीन वर्ष का सफल वैवाहिक जीवन पूर्ण करने के उपरांत इस शेष राशि का भुगतान भी उन्हें कर दिया जाता है।

बृथ सशक्तीकरण को लेकर भाजपा की मुहिम

दुर्ग। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार जिला भाजपा के पदाधिकारियों की मासिक संगठनात्मक समीक्षा बैठक कार्यालय में जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिला महामंत्री दिलीप साहू, विनोद अरोरा, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश सेन, उपाध्यक्ष शिवेंद्र परिहार सहित अन्य प्रमुख रूप से मौजूद थे। बैठक में मंडलों की संगठनात्मक गतिविधियों, आगामी कार्यक्रमों, सदस्यता विस्तार, बृथ सशक्तिकरण तथा विभिन्न अभियानों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मंडल प्रभारियों से उनके क्षेत्रों में चल रहे संगठनात्मक कार्यों की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक ने कहा कि भाजपा विश्व का सबसे बड़ा राजनैतिक संगठन है और इसकी ताकत कार्यकर्ताओं की सक्रियता, अनुशासन एवं जनसंपर्क में निहित है। बैठक में मनोज सोनी, सरिता मिश्रा, हर्षा चंद्राकर, अशोक राठी, राजीव पांडेय, मंत्री गिरीश साहू, शैलेंद्र शेंडे, नवीन पवार, नीलेश अग्रवाल, नीतेश साहू, अरूण सिंह, राजा खोखर, रितेश शर्मा सहित अन्य मौजूद थे।

सामान्य सभा में भाजपा समर्थित जिप सदस्य जितेंद्र यादव ने अफसरों की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल विधायकों की मौजूदगी में सीएम के कार्यक्रम को लेकर बवाल आरईएस के ईई ने कहा-मुझे सस्पेंड कर दो, लेकिन मैं गलत नहीं

हरिभूमि न्यूज ►►दुर्ग

जिला पंचायत सभाकक्ष में जिला पंचायत की समान्य सभा बैठक में गुरुवार को जमकर बवाल मचा। भाजपा समर्थित सदस्य जितेंद्र यादव ने अफसरों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 31 मई को हुए कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों के कामों को लोकार्पण और भूमिपूजन में शामिल किए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि जब भूमिपूजन और लोकार्पण हो चुका है, तो फिर उन्हें क्यों शामिल किया गया। इस पर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के ईई जितेंद्र मेश्राम ने कहा कि उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन पर यह निर्णय लिया गया। इसे लेकर जमकर कहासुनी हुई। बात यहां तक पहुंच गई कि जितेंद्र मेश्राम को यह कहना पड़ा कि भले ही मुझे सस्पेंड कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। उन्होंने कहा कि अनावश्यक उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। जितेंद्र यादव ने प्रशानिक कामकाज को लेकर कई प्रश्न दगे। उन्होंने नारायणपुर से ट्रांसफर होकर आए सब इंजीनियर अश्वनी द्विवेदी के दुर्ग में अटैचमेंट का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि जब उन्हें धमधा में पोस्टिंग दी गई है, तो वे दुर्ग में क्यों अटैच हैं। इसी प्रकार उन्होंने पिछले 5 महीने से जारी नहीं हुए निराश्रित, विधवा सहित पेंशन स्कीम के फंड का मुद्दा उठाया। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र नियमित रूप से नहीं खुलने को लेकर शिकायत की। बैठक में ग्रामीण



1427 स्कूलों में आरटीई की 328 सीटें रिक्त, जवाब से असंतुष्ट

सदस्यों ने जिले में संचालित 1427 स्कूलों में आरटीई की 328 सीटें रिक्त होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 1427 सीटें आरक्षित हैं, लेकिन अब भी 328 सीटें रिक्त हैं। डीईओ अरविंद मिश्रा ने इसे लेकर जवाब दिया, जिस पर सदस्य असंतुष्ट थे। इसी प्रकार हेल्थ विभाग में पिछले दिनों दौपिका गाड़ा की मौत के मामले में जानकारी चाही। इस पर हेल्थ विभाग ने कलेक्टर से आदेश पर जांच कमेटी गठित होने की जानकारी दी। जिला पंचायत सदस्य अशोक साहू ने बताया कि मकरेगा में बड़ी गड़बड़ी की जा रही है। फोटो खिंचकर ऐसे निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की शिकायत कई ग्राम पंचायतों से मिल रही है। इस पर तत्काल कड़ाई जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो। उन्होंने खरीफ सौजन की तैयारियों को लेकर कोई जानकारी नहीं दिए जाने पर नाराजगी भी व्यक्त की।

विधायक ललित चंद्राकर, साजा विधायक ईश्वर साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे सहित अन्य प्रमुख रूप से मौजूद थे। बैठक में विधायकों ने विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण विकास तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक सुझाव एवं निर्देश दिए। साथ ही विभागीय

अधिकारियों को आमजन से जुड़े मुद्दों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी प्रदान किए। बैठक में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, समाज कल्याण विभाग, खाद्य विभाग, खनिज विभाग तथा विक्सित भारत ग्राम योजना सहित विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए विस्तृत चर्चा की गई।

दुर्ग जिले में धड़ल्ले से हो रहा मुरुम खनन, जिम्मेदार मौन



हरिभूमि न्यूज ►►मिलालई

दुर्ग जिले में अवैध मुरुम खनन का कारोबार तेजी से फलफूल रहा है। कलेक्टर के निर्देश के बाद भी खुलेआम तालाबों में तीन से चार चैन माउंटैन मशीन उतारकर मुरुम खोदी जा रही है।

भिलाई आईआईटी मेन गेट के पास गुटेला भाटा में रात दिन अवैध रूप से मुरुम खोदी जा रही है। इसके साथ ही बार्सिंग में दो अलग अलग जगहों पर चैन माउंटैन से मुरुम का उत्खनन हो रहा है। जब इस बारे में एसडीएम हरबंश सिंह मिरी को फोन लगाकर जानकारी दी गई तो

उन्होंने कहा कि खनिज विभाग को वो सूचना दे दौंगे। कार्रवाई करना उनका काम है। इसके बाद जिला खनिज अधिकारी दीपक मिश्रा को फोन लगाया गया तो उन्होंने फोन काट दिया। वाट्सअप में फोटो वीडियो के साथ जानकारी देने के बाद भी उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। कुटेला भाटा और बार्सिंग के ग्रामीणों से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनके द्वारा पास के पुलिस थाना के अलावा खनिज विभाग में भी शिकायत की गई है, लेकिन खनिज अधिकारियों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

भिलाई आईआईटी मेन गेट के पास गुटेला भाटा में रात दिन अवैध रूप से मुरुम खोदी जा रही है। इसके साथ ही बार्सिंग में दो अलग अलग जगहों पर चैन माउंटैन से मुरुम का उत्खनन हो रहा है। जब इस बारे में एसडीएम हरबंश सिंह मिरी को फोन लगाकर जानकारी दी गई तो

उन्होंने कहा कि खनिज विभाग को वो सूचना दे दौंगे। कार्रवाई करना उनका काम है। इसके बाद जिला खनिज अधिकारी दीपक मिश्रा को फोन लगाया गया तो उन्होंने फोन काट दिया। वाट्सअप में फोटो वीडियो के साथ जानकारी देने के बाद भी उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। कुटेला भाटा और बार्सिंग के ग्रामीणों से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनके द्वारा पास के पुलिस थाना के अलावा खनिज विभाग में भी शिकायत की गई है, लेकिन खनिज अधिकारियों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

भिलाई आईआईटी मेन गेट के पास गुटेला भाटा में रात दिन अवैध रूप से मुरुम खोदी जा रही है। इसके साथ ही बार्सिंग में दो अलग अलग जगहों पर चैन माउंटैन से मुरुम का उत्खनन हो रहा है। जब इस बारे में एसडीएम हरबंश सिंह मिरी को फोन लगाकर जानकारी दी गई तो

नेहरू नगर में लाखों की चोरी का खुलासा अंतर्राज्यीय गिराह के छह आरोपी गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज ►►मिलालई

नेहरू नगर पश्चिम स्थित एक सूने मकान में लाखों रुपए की चोरी के मामले में सुपेला पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिराह का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के सोने, हीरे और चांदी के आभूषण, नगदी रकम, वाहन, मोबाइल फोन तथा घटना में प्रयुक्त औजार बरामद किए हैं। मामले में चोरी का माल खरीदने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।

पुलिस के अनुसार नेहरू नगर पश्चिम निवासी विनय कुमार अग्रवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 4 मई 2026 को वह अपने परिवार के साथ घर में ताला लगाकर धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। अगले दिन लौटने पर घर का मुख्य ताला टूटा हुआ मिला और अलमारी के लॉक भी क्षतिग्रस्त थे।



अज्ञात चोर घर से सोना, हीरा, चांदी के आभूषण तथा लगभग 3.40 लाख रुपये नकद लेकर फरार हो गए थे। शिकायत पर थाना सुपेला में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने विशेष टीम गठित कर घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगोले। तकनीकी साक्ष्यों और जांच के आधार पर मुख्य आरोपी नेरट निवासी हारिम और दिल्ली निवासी मोहम्मद नाफिर हुसैन सहित उनके सहयोगियों मेरठ युपी निवासी मोहम्मद कासिम, सलीम, मोहम्मद बिलााल और दिन मोहम्मद की पहचान की गई। जांच में सामने आया कि आरोपी पहले सूने मकानों की रेकी करते थे और फिर सुनियोजित तरीके से चोरी की

वारदात को अंजाम देते थे। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी के आभूषण मेरठ के एक ज्वेलर्स को बेचने तथा चोरी की रकम आपस में बांटने की बात स्वीकार की। इसके बाद पुलिस टीम ने विभिन्न राज्यों में दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया और चोरी का माल बरामद किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोने एवं हीरे के आभूषण, चांदी के आभूषण, नगदी रकम, जुपिटर और सैटेलाइट वाहन, मोबाइल फोन, ताला तोड़ने के औजार सहित अन्य सामग्री जब्त की है। विवेचना के दौरान प्रकरण में अन्य प्रासंगिक धाराएं भी जोड़ी गईं। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर भाजपा का आयोजन

सरकार के 12 वर्ष पूर्ण, सांसद विजय ने किया हवन-पूजन

हरिभूमि न्यूज ►►मिलालई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भाजपा जिला भिलाई के निर्देशन में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सांसद विजय बघेल के नेतृत्व में महाराणा प्रताप भवन सेक्टर-7 भिलाई और रुक्खड़ नाथ मंदिर नाराधा में हवन-पूजन कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर सांसद द्वारा पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ महाराणा प्रताप भवन में भगवान हनुमान, भगवान शिव, प्रभु श्रीराम-जानकी, माता पार्वती, भगवान गणेश एवं मां जगदंबा की विधिवत पूजा-अर्चना के साथ हुआ। सांसद विजय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत ने विकास, सुशासन और जन कल्याण की नई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यह कालखंड केवल सरकार की उपलब्धियों का नहीं बल्कि देश के 140 करोड़ नागरिकों के सामूहिक संकल्प और विश्वास की सफलता का



प्रतीक है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम में अहिलारा विधायक डोमनलाल कोसैवाड़ा, भाजपा जिला प्रभारी रामजी भारती, भाजपा जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन, कार्यक्रम संयोजक वीरेंद्र साहू, सांसद प्रतिनिधि प्रमोद सिंह, सहसंयोजक दया सिंह, सीरीश अग्रवाल, रुक्खड़ नाथ मंदिर नाराधा के पूजा प्रभारी रविशंकर सिंह सहित भाजपा के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

दुर्ग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद पर 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के बड़ता भारत, बदलता भारत अभियान के तहत दुर्ग जिला भाजपा ने विशेष पूजा-अर्चना और मंगलकामना कार्यक्रम आयोजित किया। जिला भाजपा कार्यालय के पीछे स्थित हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य तथा राष्ट्र की किरंतर प्रगति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई। जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में भगवान हनुमान की विधिवत पूजा-अर्चना की गई। इस दौरान हनुमान चालीसा एवं आरती का पाठ कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ, दीर्घायु और यशस्वी जीवन की कामना की गई। देश की उन्नति, समृद्धि और जनकल्याण के लिए भी प्रार्थना की गई। जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 12 वर्षों में विकास, सुशासन, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा के नए आयाम स्थापित किया है। कार्यक्रम में जिला महामंत्री दिलीप साहू, विनोद अरोरा, जिला उपाध्यक्ष सरिता मिश्रा, राजीव पांडेय, शिव चंद्राकर आदि मौजूद थे।

सीएसवीटीयू में डिप्लोमा माइनिंग व फायर सेफ्टी पाठ्यक्रमों में नहीं होंगे दाखिले

हरिभूमि न्यूज >>> मिलाई

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (सीएसवीटीयू) के विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग (यू.टी.डी.) में संचालित डिप्लोमा माइनिंग एवं डिप्लोमा फायर सेफ्टी पाठ्यक्रम इस वर्ष तकनीकी शिक्षा संचालनालय (डीटीई) की काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सके हैं। इसके कारण डीटीई काउंसिलिंग में शामिल विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय परिसर में इन रोजगारपरक पाठ्यक्रमों में प्रवेश का अवसर नहीं मिला पाएगा। प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवश्यक जानकारी समय पर प्रेषित नहीं किए जाने के कारण दोनों पाठ्यक्रम काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर रह गए। वहीं पाठ्यक्रमों को लेकर लंबे समय से चल रही प्रशासनिक एवं अधोसंरचनात्मक चुनौतियां भी सामने आ रही हैं।

ख़बर संक्षेप

तालाब में मृत मिली सैकड़ों मछलियां

भिलाई। कैप-2 स्थित शारदा पारा तालाब में सैकड़ों की संख्या में मछलियों की मौत होने का मामला सामने आया है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, तालाब में नालियों का गंदा पानी मिलने और पानी की गुणवत्ता खराब होने से यह स्थिति बनी है, जिसके बाद इलाके में गंभीर बीमारी और संक्रमण फैलने का खतरा मंडरा रहा है। तालाब में भारी संख्या में मछलियां मृत अवस्था में पाई गई हैं, जो जल प्रदूषण के गंभीर स्तर को दर्शाती हैं। रहवासियों का आरोप है कि आसपास की दो बड़ी नालियों का दूषित पानी सीधे तालाब में गिर रहा है, जिससे जलीय जीवों का दम घुट रहा है। इस दूषित पानी के सड़ने और बदबू के कारण स्थानीय लोगों को हेजा और अन्य संक्रामक बीमारियों के फैलने की चिंता सता रही है।

तालाब की सफाई और नालियों के पानी को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा त्वरित कदम उठाने की मांग स्थानीय निवासियों द्वारा की गई।

छत्तीसगढ़ शिक्षक फेडरेशन में जिला सचिव बने तिवारी

पाटन। छत्तीसगढ़ शिक्षक फेडरेशन की बैठक में सर्वसम्मति से लक्ष्मीकांत तिवारी को नया जिला सचिव नियुक्त किया गया। उनकी इस नियुक्ति से जिले के शिक्षकों में हर्ष है। छत्तीसगढ़ शिक्षक फेडरेशन फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष राजेश चटर्जी, दुर्ग जिलाध्यक्ष चंचल द्विवेदी, विकासखंड पाटन अध्यक्ष प्रदीप कुमार वर्मा आदि ने बधाई दी है।

खुर्सीपार वार्ड में सीवरेज, सफाई व पेयजल व्यवस्था का निरीक्षण



हरिभूमि न्यूज >>> मिलाई

नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने जून-4 खुर्सीपार अंतर्गत सिवरेज लाइन संधारण, नाला सफाई, पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट एवं प्रस्तावित विकास कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने तथा नागरिक सुविधाओं को बेहतर

बनाने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त, स्थानीय पार्षद सह उप नेता प्रतिपक्ष दया सिंह के साथ वार्ड क्रमांक-44 लक्ष्मी नारायण वार्ड में चल रहे सिवरेज लाइन संधारण कार्य का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही जिन घरों के समीप से सिवरेज लाइन गुजर रही है और मरम्मत की आवश्यकता है, उसे तत्काल ठीक कराने कहा।

साफ-सफाई को लेकर सख्ती

आयुक्त ने स्पष्ट किया कि यदि संबंधित पक्ष स्वयं कार्य नहीं कराते हैं तो निगम द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान हाल ही में कराई गई नाला सफाई व्यवस्था का भी अवलोकन किया गया। आयुक्त ने सफाई कार्यों को नियमित रूप से जारी रखने तथा बरसात के मौसम को देखते हुए जलभराव की स्थिति से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। केनाल रोड क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए आयुक्त ने प्रस्तावित सर्विस रोड निर्माण स्थल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण से क्षेत्र के नागरिकों को सुगम एवं सुरक्षित यातायात सुविधा उपलब्ध होगी तथा आवागमन में होने वाली परेशानियां कम होंगी।

निगम ने चलाया उत्पल के अवैध कब्जे पर बुलडोजर

हरिभूमि न्यूज >>> मिलाई

नगर पालिक निगम भिलाई के जून-4 अंतर्गत नंदिनी रोड, गुप-ए, भूखंड क्रमांक 02 के पूर्व दिशा में उत्पल घोष द्वारा व्यवसाय के लिए किए गए अवैध कब्जे को नगर पालिक निगम ने हटाया। निगम को इस संबंध में शिकायत मिली थी कि उक्त स्थल पर निर्माणकर्ता द्वारा आवागमन बाधित कर व्यवसाय संचालित किया जा रहा है। नगर पालिक निगम को जानकारी मिला कि निर्माणकर्ता को पहले भी उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा पारित आदेश का पालन करते



हुए अवैध संरचना हटाने के लिए कई बार नोटिस और अंतिम सूचना जारी की गई थी, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। इस पर निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देशानुसार जून-4 के राजस्व विभाग, बेदखली टीम एवं थाना छावनी के पुलिस बल की मौजूदगी में स्थल पर कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई। निगम



दोनों पाठ्यक्रम एसईसीएल से थी प्रायोजित

सूत्रों के अनुसार इन दोनों पाठ्यक्रमों को साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (एसईसीएल) द्वारा पूर्णतः प्रायोजित करने की प्रक्रिया भी प्रचलित थी। जिससे विश्वविद्यालय पर वित्तीय भार कम होना था और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधा मिलने की संभावना थी। इसके बावजूद भवन निर्माण में विलंब तथा संचालन हेतु आवश्यक कक्षों के आबंटन में देरी के कारण प्रयोगशालाएं (लैब) समय पर पूर्ण नहीं हो सकीं। इसलिए भी प्रभाव पड़ा।

काउंसिलिंग में दोनों कोर्स की जानकारी समय पर नहीं भेजी गई , प्रशासनिक निर्णयों, अधोसंरचना और प्रवेश नीति पर उठे सवाल

दोनों विषयों में प्रवेश भी कम

माइनिंग व सेफ्टी विषयों पर प्रवेश संख्या कम होने को लेकर भी अलग-अलग पक्ष सामने आ रहे हैं। प्रदेश के अन्य शासकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में जहां विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत कम शुल्क पर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलता है, वहीं सीएसवीटीयू में लगभग 45 हजार रुपये जैसे अधिक शिक्षण शुल्क तथा छात्रावास परिसर की अनुपलब्धता के कारण प्रवेश क्षमता के मुकाबले नामांकन काफी कम रहा। इससे इन पाठ्यक्रमों की व्यवहारिक उपयोगिता और संचालन मॉडल पर भी प्रश्न उठ रहे हैं।

एआईसीटीई की मान्यता को स्पष्ट करने की जरूरत

एआईसीटीई मान्यता को लेकर भी स्थिति स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय अधिनियम, विनियम, परिनियम एवं अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिए पृथक रूप से एआईसीटीई अथवा यूजीसी मान्यता की आवश्यकता संबंधी प्रावधानों की व्याख्या अलग-अलग स्तर पर की जा रही है। हालांकि देश के बाहर या नियामकीय आवश्यकताओं वाले क्षेत्रों में ऐसी मान्यता का महत्व हो सकता है।

छत्तीसगढ़ में ये महत्वपूर्ण

पाठ्यक्रम

खनिज संपदा से समृद्ध छत्तीसगढ़ राज्य में माइनिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र से जुड़े पाठ्यक्रम का कमजोर होना चिंता को विषय माना जा रहा है। राज्य शासन की मंशा रही है कि स्थानीय विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा उपलब्ध हो और शिक्षा सेवा का माध्यम बने, केवल व्यवसायिक गतिविधि नहीं।अब आवश्यकता इस बात की है कि विश्वविद्यालय प्रशासन पूरे मामले की समीक्षा करते हुए यह तय करे कि इन पाठ्यक्रमों को किस प्रकार मजबूत किया जाए, अधूरी अधोसंरचना को पूरा किया जाए और विद्यार्थियों के हित में प्रवेश व्यवस्था को पुनः प्रभावी बनाया जाए।

अंबेडकर भवन में लाखों की चोरी की शिकायत कलेक्टर से



हरिभूमि न्यूज >>>मिलाई

भिलाई-चरोदा नगर निगम के वार्ड 9 स्थित अंबेडकर भवन में हुए चोरी की मामले की शिकायत कलेक्टर से की गई है।

कलेक्टर से इस मामले में सीधे हस्तक्षेप कर एफआईआर दर्ज कराने और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही दोषी अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई करने किया आग्रह किया। कलेक्टर को आम आदमी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जसप्रीत सिंह और चरोदा भिलाई लोकसभा उपाध्यक्ष पंकज तिवारी ने शिकायत पत्र सौंपा है।

कलेक्टर को शिकायत में बताया कि वर्ष 2022 में लगभग 2.20 करोड़ रुपए की भारी-भरकम लात से आम जनता की गाढ़ी कमाई से अंबेडकर भवन का निर्माण कराया गया था। भवन उद्घाटन के बाद देखरेख के अभाव में लगातार चोरियां होती रही। वर्तमान में यहाँ से जनता के पैसे से खरीदा गया लगभग 20 लाख का सरकारी सामान जैसे 64 पंखे, 172 ट्यूबलाइट, 224 बल्ब, रिछड़ी-दरवाजे और अन्य

वियुत उपकरण चोरी हो चुका है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि नगर निगम द्वारा गठित आंतरिक जांच दल ने महीनों पहले अपनी रिपोर्ट आयुक्त को सौंप दी थी। इसके बावजूद निगम प्रशासन आज तक स्थानीय थाने में कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। अधिकारियों की यह रहस्यमयी चुप्पी सीधे तौर पर चोरों को संरक्षण देने और भ्रष्टाचार को दबाने की साटगाठ की ओर इशारा करती है। कलेक्टर को ज्ञापन

सौंपने वालों में पंकज तिवारी, हरचरण, धर्मेन्द्र चौधरी, रामपाल, जसप्रीत सिंह, मनीष, सोनू, शिवा, देवेंद्र आदि शामिल थे। पंकज तिवारी ने कहा कि इन्हने बड़े नुकसान के बाद भी एफआईआर दर्ज न कराना एक बड़े घोटाले का संकेत है। क्या वास्तव में 20 लाख का सामान कभी उस भवन में लगाया भी गया था या सिर्फ कागजों पर फर्जी खरीदी दिखाकर जनता के पैसे का गवन किया गया है। अब चोरी का बहाना बनाकर अपनी चमड़ी बचाने की कोशिश की जा रही है।

अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति गठित

हरिभूमि न्यूज >>> बेमेतरा

अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कराने के नाम पर कथित रूप से रिश्तत मांगने के मामले में जिला प्रशासन ने गंभीर रुख अपनाया है। शिकायत प्राप्त होने के बाद कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित कर दिया है।

समिति को एक सप्ताह के भीतर जांच पूरी कर स्पष्ट अभिमत सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम सिंघनपुरी निवासी विनय बंजारे ने 11 जून 2026 को जिला प्रशासन की लिखित शिकायत सौंपते हुए संबंधित कर्मचारी पर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि दिलाने के एवज में धनराशि मांगने का आरोप लगाया था। शिकायत के आधार पर कलेक्टर कार्यालय ने 12 जून को जांच समिति गठित करने का आदेश जारी किया।

गठित समिति में वित्त शाखा की प्रभारी अधिकारी दिव्या पोटाई, सहायक आयुक्त आदिवासी

विकास अभिषेक जायसवाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग चंद्रेश सिसोदिया तथा लीड बैंक अधिकारी सुशील सिंह को शामिल किया गया है। समिति शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करेगी तथा मार्च 2026 से वर्तमान तक अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्वीकृत और लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा करेगी। जारी आदेश के अनुसार जांच दल पात्रता संबंधी दस्तावेजों, आवेदन प्रक्रिया और भुगतान से जुड़े अभिलेखों का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेगा। बताया जा रहा है कि न्यायालय परिसर में पदस्थ एक कर्मचारी पर प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कराने के नाम पर धनराशि मांगने के आरोप लगाए गए हैं। मामले से जुड़ा वीडियो और अन्य तथ्यों के सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश जारी किए हैं। इस कार्रवाई को प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब जिले भर की निगाहें जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिसके आधार पर दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध आगे की प्रशासनिक कार्रवाई तय की जाएगी।

31 से अलग रह रही पत्नी ने पति की संपत्ति पर पुत्र के लिए दावा कर रही

हरिभूमि न्यूज >>> नांदघाट

पति के छोड़ने के 31 साल बाद पत्नी अपने पति के पास लौट करअपने पुत्र के हक के लिए दावा कर रही है । पिता अपने बच्चे को अपना खून मानने से इनकार कर रहा है । बुआ अपने भतीजे की शिकायत कर रही है और बहु ने तो एक कदम आगे बढ़कर अपने ससुर

पर छेड़छाड़ कुट्टाई के समीन आरोप की लिखित शिकायत की है । एक दूसरे का शिकायतों का पुलंदा पुलिस के सामने है ।और घर के आपसी विवाद रिश्तों का जटिल ताने बाने को लेकर हलकान और परेशान है । मामला नांदघाट पुलिस का है थाना नादघाट अंतर्गत ग्राम मेहना का है । जहां के निवासी पवन कुमार पिता तिहारी की शादी सेंदरी भाटापारा की कमलेश के साथ 1995 में हुई थी कमलेश के अनुसार उसके पति पवन कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी उसके बावजूद उसने डेढ़ साल ससुराल में पवन के साथ बिताए फिर वह मायके आ गई विवाह विच्छेद हो गया पर उसके पेट में पवन का बच्चा था जिसका जन्म 1996 में हुआ फिर कुछ दिनों बाद कमलेश की दूसरी शादी चंदनू में तिजेलाल के साथ हुई थी । लेकिन वह भी शादी ज्यादा दिन नहीं चली तिजेलाल के 2 साल में देहांत के बाद कमलेश ने मेहनत मजदूरी कर अपने मायके में ही रहकर अपने पुत्र देवेंद्र की परवरिश की उसकी उसकी शादी ब्याह किया फिर अपने पुत्र के पिता पवन के पास उसका अधिकार दिलाने आ गई पति पवन की मेहना में उसके हिस्से की तीन एकड़ कृषि

भूमि और घर है जिसमें वह अपनी बहन मोगरा के संरक्षण में जीवन निर्वाह कर रहा है ।परिजनों के दबाव में कमलेश उसका पुत्र देवेंद्र और अपने परिवार के साथ एक हिस्से में निवास करने लगी है लेकिन .कमलेश का आरोप है कि पवन अपनी पत्नी अपनी बहन मोगरा के बहकावे मेंआकर न केवल उसको पूर्व पत्नी होने तथा देवेंद्र को भी अपना जैविक पुत्र मानने से इनकार कर रहा है ।

आपतिजना हरकत की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की

दिनांक 24 / 5 / 26 उसका पुत्र देवेंद्र तथा उसकी पत्नी से मारपीट कर घर में तोड़फोड़ कर रहा है । इसके अलावा देवेंद्र की पत्नी ने भी अपने ससुर के विरुद्ध गाली गलौज छेड़छाड़ आपतिजना हरकत की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है ।दूसरी ओर पवन ने भी अपनी पूर्व पत्नी कमलेश बेटे देवेंद्र एवं बहु अंजु पर भी मारपीट उत्पीड़न जान का खतरा बताते हुए एसपी से ही शिकायत की है ।भाई की तरह बहन मोगरा ने भीअपने कथित भतीजे देवेंद्र भाभी कमलेश और बहु अंजु पर पवन और उसके साथ बहन मोगरा पर भी मन गाली गलौज व उत्पीड़न प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं । तथा कार्यवाही की मांग की है। एक दूसरे की सभी शिकायतें पुलिस के पास है अब पुलिस द्वारा जांच के लिए सभी पक्षों को क्रमशः आहूत कर पता साजी की जा रही है ।अब किसकी शिकायत पर किसके किसके विरुद्ध क्या कार्यवाही होती है। अनुसंधान पश्चात ज्ञात होगा । पर मामले की जटिलता कौतुहल का विषय बना हुवा है।

HEALTH TOWN

DR. ABHIMANYU'S
AYURVEDA MULTISPECIALITY HOSPITAL
PAIN (PANCHAMAHA) / PILES / PREGA / GYNAE / SKIN

Piles Care Clinic
Unit of Dr. Abhimanyu's Pain Relief Center
ISO 9001:2015 Certified Clinic

> रात रोग > घुटने के दर्द > पीठ व कमर दर्द > रूमिनेट्रडिफिट > लिगामेंट के दर्द

> लार्डोसिस > गोलफ एल्बो > क्रोउनल रोडर > राश्टीर के जकड़न

कंधा, गर्दन, मांसपेशियां व सभी प्रकार के दर्द का इलाज

9 सिटी सेंटर - कृष्णा टॉकीज के सामने, सभाग कौलोनी रायपुर (छ.ग.) ☎ 9826446666

9 सेक्टर -7 कमल विहार, रायपुर (छ.ग.) ☎ 95224-68664, 62622-22003

विज्ञापन हेतु संपर्क करें > 0771-4242213, 7987119756, 9303508130

कृषि विभाग की कार्यप्रणाली से नाराज व्यापारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी

हरिभूमि न्यूज़ ►► बेमेतरा

जिला कृषि व्यापारी संघ ने जारी बयान में कृषि विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि औचक निरीक्षण के नाम पर जिले के कृषि व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। संघ अध्यक्ष सिद्धीक खान सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि व्यापारियों ने खाद व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं को लेकर पूर्व में सांकेतिक रूप से एक दिवसीय व्यापार बंद कर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन समस्याओं के निराकरण के बजाय विभाग औपचारिक खामियों का हवाला देकर कार्रवाई कर व्यापारियों पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है।

उन्होंने कहा कि जिले के सभी कृषि व्यापारी इस रवैये की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। यदि विभाग का यही रुख बना

खबर संक्षेप

साहू समाज ने दिया हरित भविष्य का संदेश

सेलूद। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. नरेंद्र साहू के आह्वान पर परिक्षेत्रीय साहू संघ अरसनारा एवं स्थानीय साहू समाज सेलूद के संयुक्त तत्वावधान में धान खरीदी केंद्र सेलूद परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रमुख सलाहकार खेमलाल साहू ने कहा कि प्रदेश साहू संघ द्वारा प्रकृति संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सामाजिक सरोकार से जुड़ी यह पहल अत्यंत सराहनीय है। इस अवसर पर प्रमुख सलाहकार खेमलाल साहू, परिक्षेत्रीय अध्यक्ष किशन हिरवानी, न्याय प्रकोष्ठ संयोजक कोशल बनपेला, उपाध्यक्ष संतोष साहू, अंकेक्षक शशिभूषण साहू, संगठन सचिव अर्जुन साहू, सोसायटी अध्यक्ष तामन साहू, महिला संयोजिका खेमीन साहू, प्रचार सचिव रवि साहू, अनिल बनलाल, स्थानीय अध्यक्ष जयंत साहू, उपसरपंच राकेश साहू आदि उपस्थित थे।

सरपंच ने की वृद्धा पेंशन भुगतान की मांग

अंडा। अंडा क्षेत्र में वृद्धा पेंशन योजना के हितप्राप्तियों को पिछले लगभग 5 माह से पेंशन राशि का भुगतान नहीं होने के कारण बुजुर्ग नागरिकों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पेंशन पर निर्भर वृद्धजन अपनी दैनिक आवश्यकताओं, दवाइयों एवं अन्य जरूरी खर्चों को पूरा करने में परेशानी महसूस कर रहे हैं।

कुष्ठ उन्मूलन मासिक सघन अभियान

15 से, 4 ब्लकों में घर-घर होगा सर्वे

हरिभूमि न्यूज़ ►► बेमेतरा

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिले में 15 जून से 15 जुलाई तकसघन कुष्ठ खोज अभियान चलाया जाएगा। जिले को कुष्ठ मुक्त बनाने के लिए समुदाय स्तर पर छिपे हुए कुष्ठ

- लक्ष्य कुष्ठ के छिपे रोगियों की पहचान कर विकलांगता रोकना जाएगा :** कलेक्टर
- रोगियों की प्रारंभिक अवस्था में पहचान करना इस अभियान का मुख्य लक्ष्य है। समय पर पहचान एवं MDT से पूर्ण उपचार शुरू कर रोग के प्रसार

को रोका जा सकता है तथा Grade-2 विकलांगता की दर को शून्य तक लाया जा सकता है। वर्तमान में जिले का प्रीवैलेन्स रेट 1 लाख आबादी पर 1 लाने का लक्ष्य है। दी गई जानकारी अनुसार जिले के सभी 4 विकासखण्डों - बेमेतरा, बेरला, नवागढ़, साजा के 100% ग्रामीण क्षेत्रों एवं सभी नगरीय निकायों के वार्डों में घर-घर सर्वे किया जाएगा।

इस अभियान के लिए दल गठित किए गए हैं। जिसमें एएनएम,एमपीडब्ल्यू , सीएचओ,मितानिन व आशा कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है। टीम घर-घर जाकर परिवार के प्रत्येक सदस्य की

कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा-किसानों के नाम पर भ्रम फैलाकर अपनी विफलताओं को छिपाने का प्रयास

कांग्रेस का किसान आंदोलन राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की कवायद : भाजपा

हरिभूमि न्यूज़ ►► बेमेतरा

जिला किसान कांग्रेस द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर किए गए प्रदर्शन पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के आंदोलन को राजनीतिक प्रायोजित कार्यक्रम बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा नहीं, बल्कि अपनी समापत होती राजनीतिक प्रासंगिकता को बचाना है।

भाजपा नेताओं ने कहा कि जिस कांग्रेस का इतिहास किसानों के साथ छल, झूठे वादों और विश्वासघात से भरा रहा है, उस किसानों के नाम पर राजनीति करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। नेताओं ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की जनता ने

कांग्रेस को उसके वादाखिलाफी और किसान विरोधी मानसिकता के कारण सत्ता से बाहर किया था। वहीं मुख्यमंत्री

कृषि व्यापारी संघ ने कार्रवाई को बताया दबाव बनाने की कोशिश

किसानों को दुकान पर ले जाकर हंगामा कराने का आरोप

संघ ने कृषि विभाग के सहायक संचालक श्याम लाल साहू पर भी आरोप लगाया कि छाल ही में कुछ किसानों को एक कृषि व्यापारी की दुकान पर ले जाकर हंगामा कराया गया। संघ ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि यदि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं दोहराई गईं तो व्यापारी भी विरोध दर्ज कराने के लिए बाध्य होंगे। व्यापारियों का यह भी कहना है कि कुछ लोग किसान संगठन के नाम पर व्यापारियों को ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहे हैं और विभाग की कार्यप्रणाली से ऐसे तत्वों को बढ़ावा मिल रहा है।

अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी

संघ ने चेतावनी दी है कि यदि विभाग शीघ्र ही समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम नहीं उठाता, तो जिले के सभी कृषि व्यापारी सामूहिक रूप से अपनी दुकानों में ताला लगाकर चाबियां डीडीए को सौंप देंगे और अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू करेंगे। संघ ने कहा कि ऐसी स्थिति की पूरी जिम्मेदारी कृषि विभाग बेमेतरा की होगी।



खाद आपूर्ति व्यवस्था को बताया समस्या की जड़

कृषि व्यापारी संघ के अनुसार, पिछले माह खाद व्यापार में आ रही समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया था। इसमें खाद निर्माता कंपनियों एवं जिले के बाहर स्थित रैक हैंडलिंग थोक विक्रेताओं द्वारा खुदरा व्यापारियों पर थोपे जा रहे अतिरिक्त लदान पर रोक लगाने तथा उर्वरक को सीधे प्लांट ऑफ सेल तक पहुंचाने की मांग की गई थी। संघ का आरोप है कि इन मूल समस्याओं पर कार्रवाई करने के बजाय विभाग छोटे व्यापारियों को निशाना बना रहा है। व्यापारियों ने सवाल उठाया कि फेरी लगाकर नकली खाद एवं दवाइयों की बिक्री करने वालों तथा बिजोलियों के खिलाफ प्रमावी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, जबकि विधिवत लाइसेंसधारी व्यापारियों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है।

शिक्षा व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का बड़ा हमला: स्कूलों को खंडहर बनने दे रही भाजपा सरकार

स्कूलों की छतें दो साल से टूटी और शिक्षकों की कमी से शिक्षा बदहाल

हरिभूमि न्यूज़ ►► बेमेतरा

जिले की शिक्षा व्यवस्था को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जिला कांग्रेस कमटी अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने भाजपा सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर

- पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा का आरोप-वरमराई व्यवस्था बच्चों के भविष्य से खिलवाड़**

तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि बेमेतरा में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह उपेक्षा का शिकार हो गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में शिक्षा के नाम पर केवल दिखावा किया जा रहा है, जबकि जमीनी स्तर पर स्कूलों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। छाबड़ा ने कहा कि कुछ ही दिनों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन जिला मुख्यालय के दो महत्वपूर्ण विद्यालय आज भी अपनी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। इनमें जिले का एकमात्र शताब्दी विद्यालय और स्वामी आत्मानंद स्मृति हिंदी माध्यम कन्या विद्यालय शामिल हैं, जिनकी छतें लगभग दो वर्ष पहले आए तूफान में क्षतिग्रस्त हो गई थीं।



मुख्यमंत्री की समाएं हुई, पर नहीं सुधरे स्कूलों की हालत

पूर्व विधायक ने कहा कि बेमेतरा के बेसिक स्कूल मैदान में मुख्यमंत्री की दो से तीन बड़ी समाएं आयोजित हो चुकी हैं। इन समाओं के दौरान मुख्यमंत्री स्वयं इन विद्यालयों की जरूरत स्थिति देख चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिले के सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान सरकारी उदासीनता के कारण बदहाली का सामना कर रहे हैं। छाबड़ा ने यह भी कहा कि इन दोनों विद्यालयों के ठीक सामने जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय स्थित है। जिले के शीर्ष शिक्षा अधिकारी प्रतिदिन इन भवनों की खराब स्थिति देखते हैं, लेकिन मरम्मत और संरक्षण के लिए कोई प्रमावी पहल नहीं की जा रही है। इससे प्रशासनिक संवेदनशीलता पर भी प्रश्नचिह्न लग रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि इतने लंबे समय बाद भी इन भवनों की मरम्मत नहीं कराई गई, जिससे सरकार की शिक्षा के प्रति गंभीरता पर सवाल खड़े होते हैं। अपने बयान में छाबड़ा ने स्थानीय भाजपा जनप्रतिनिधियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधियों का ध्यान शिक्षा और विकास जैसे मुद्दों से हटकर केवल राजनीतिक गतिविधियों और कमीशनखोरी पर केंद्रित हो

गया है। यही वजह है कि जिले की महत्वपूर्ण शैक्षणिक समस्याएं वर्षों से लंबित हैं। उन्होंने मांग की कि नए शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने से पहले क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की तत्काल मरम्मत कराई जाए, रिक्त शिक्षकीय पदों को भरा जाए तथा स्वामी आत्मानंद विद्यालयों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाई जाए, ताकि विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित रह सके।

लंबित अपील को समाप्त बताने पर साहू समाज में फिर विवाद

हरिभूमि न्यूज़ ►► बेमेतरा

जिला साहू संघ बेमेतरा में चुनावी विवाद को लेकर चल रहा गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। 11 जून को जिला साहू संघ भवन में आयोजित आमसभा के बाद समाज के भीतर विवाद एक बार फिर सार्वजनिक रूप से सामने आ गया है। आमसभा में प्रस्तुत की गई जानकारी पर आपत्ति जताते हुए जिला साहू संघ के जिलाध्यक्ष प्रत्याशी रहे गेंदराम साहू ने प्रेस वक्तव्य जारी कर समाज को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने की बात कही है। पूर्व जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि आमसभा के दौरान समाज के सक्षम पूर्व चुनाव विवाद एवं उससे संबंधित कानूनी प्रकरण की स्थिति को लेकर भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की गई। उनके अनुसार सभा में यह बताया गया कि फर्म्स एवं सोसायटीज विभाग में चल रहा विवाद पूरी तरह समाप्त हो चुका है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण खारिज कर दिया गया है। साथ ही तत्काल प्रभार (चार्ज) सौंपने की मांग करते हुए अन्यथा एफआईआर एवं कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। गेंदराम साहू ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा कि चुनाव विवाद से

जुड़ा मामला अभी समाप्त नहीं हुआ

है। उन्होंने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप संबंधित प्रकरण में विधिवत अपील प्रस्तुत की गई है, जो वर्तमान में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि जब तक अपील पर अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक विवाद समाप्त होने का दावा करना तथ्यों के विपरीत है। ऐसी स्थिति में किसी भी पक्ष द्वारा यह प्रचारित करना कि सभी कानूनी अधिकार समाप्त हो चुके हैं, समाज को वास्तविक स्थिति से दूर ले जाने का प्रयास है।

समाज में बही हलचल समाधान की प्रतीक्षा

जिला साहू संघ की आमसभा के बाद सामने आए इस नए घटनाक्रम ने समाज के भीतर चल रहे विवाद को फिर चर्चा का विषय बना दिया है। एक पक्ष जहां विवाद समाप्त होने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरा पक्ष कानूनी प्रक्रिया जारी रहने की बात कर रहा है। ऐसे में अब समाज के लोगों की निगाहें संबंधित प्राधिकारी के अंतिम निर्णय पर टिकी हैं, जिससे लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद का स्थायी समाधान निकल सके।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान जरूरी

पूर्व जिलाध्यक्ष ने कहा कि किसी भी सामाजिक संगठन में मतभेद और विवाद होना अजमाव्य नहीं है, लेकिन उनका समाधान वैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ही होना चाहिए। लंबित मामलों को समय से पहले समाप्त घोषित करने से समाज के सदस्यों के बीच भ्रम और गलतफहमी पैदा होती है। उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक सदस्य को सही और प्रमाणिक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। किसी भी मंच से अशुद्ध या एकपक्षीय जानकारी देना संगठनात्मक मर्यादों के अनुरूप नहीं माना जा सकता।

ताला तोड़ने व धमकी देने पर भी जताई चिंता

गेंदराम साहू ने आमसभा के दौरान जिला साहू संघ भवन के ताले तोड़े जाने तथा कुछ व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक रूप से धमकीपूर्ण और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किए जाने की जानकारी मिलने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी घटनाएं हुई हैं तो यह समाज की परंपराओं, संगठनात्मक अनुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। उन्होंने जिम्मेदार पदाधिकारियों से संवाद, सहमति और वैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से समाधान निकालने का आग्रह करते हुए कहा कि दबाव और धमकी की राजनीति किसी भी सामाजिक संगठन के हित में नहीं है। उन्होंने समाज के पदाधिकारियों, वरिष्ठजनों और सदस्यों से अपील की कि किसी भी विवाद पर अंतिम निष्कर्ष निकालने से पहले आधिकारिक अभिलेखों, न्यायालयीन आदेशों और लंबित अपील की वास्तविक स्थिति का अवलोकन अवश्य करें।

युवा खेल के साथ सभी क्षेत्रों में दिखाए प्रतिभा पाटन। मारुति क्लब,एनसीसी

एवं ग्रामवासियों के तत्वावधान में ग्रामीण स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई। जिसमें मुख्य अतिथि अशोक साहू पूर्व उपाध्यक्ष एवं विधायक प्रतिनिधि जिप दुर्गा थे। अध्यक्षता सोनारी राजू वर्मा सरपंच ने की। विशेष अतिथि नोमिन ठाकुर सदस्य जिप दुर्गा,राजेश ठाकुर अध्यक्ष ब्र्यॉक कांग्रेस, दिनेश साहू जनपद सदस्य, फुलेश्वर वर्मा, भुवन साहू, मनोष वर्मा और मनोज वर्मा ने वीर हनुमान की पूजा अर्चना कर कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि जिप दुर्गा के पूर्व उपाध्यक्ष अशोक साहू ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए खेल हमेशा खेल भावना से ओतप्रोत हो, यह खेल जोश नहीं होश से खेलने वाला खेल है।

बेमेतरा हरिभूमि 14

रहा तो आने वाले दिनों में व्यापारी डीडीए कार्यालय का घेराव करेंगे तथा सामूहिक रूप से व्यापार बंद कर दुकानों की चाबियां विभाग को सौंपने और अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। कृषि व्यापारी संघ ने मांग की है कि कृषि विभाग छोटे व्यापारियों को परेशान करना बंद करे और खाद निर्माता कंपनियों तथा रैक हैंडलिंग डीलरों पर कार्रवाई कर खुदरा विक्रेताओं तक बिना अनावश्यक लदान के उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

संघ का दावा है कि इस विषय पर कई बार डीडीए से समय मांगकर निर्माता कंपनियों, थोक डीलरों और स्थानीय खुदरा विक्रेताओं की संयुक्त बैठक कराने का आग्रह किया गया, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई। इसके विपरीत स्थानीय व्यापारियों पर एकपक्षीय कार्रवाई की जा रही है।

नवीन शिक्षक संघ ने मांगी टीईटी बीएड में राहत

हरिभूमि न्यूज़ ►►उतई

नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व में संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग दुर्ग को ज्ञापन सौंपकर वर्ष 2017 में लागू किए गए टीईटी एवं बी.एड. संबंधी प्रावधानों में राहत प्रदान करने की मांग की है। संघ ने मांग की है कि वर्ष 2017 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी एवं बी.एड. की अनिवार्यता से पूर्ण छूट दी जाए तथा वर्ष 2017 से 2026 के बीच बिना टीईटी एवं बी.एड. के पदेनति प्राप्त शिक्षकों के समान शेष पात्र शिक्षकों को भी राहत प्रदान की जाए।

ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2017 में एनसीटीई द्वारा संशोधन कर प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए टीईटी तथा कुछ पदों के लिए बी.एड. योग्यता को अनिवार्य किया गया था। किंतु इस संबंध में व्यापक जागरूकता अभियान, स्पष्ट प्रशासनिक दिशा-निर्देश एवं समयबद्ध सूचना का अभाव रहा, जिसके कारण प्रदेश के अनेक शिक्षक इन प्रावधानों से अनभिज्ञ रहे। संघ ने यह भी कहा कि वर्ष 2017 से 2026 तक स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अनेक शिक्षकों को बिना टीईटी एवं बी.एड. के पदेनति प्रदान की गई, ऐसे में अब शेष बचे शिक्षकों को इन योग्यताओं के आधार पर पदेनति एवं सेवा लाभों से वंचित करना समानता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होगा। संघ ने मांग की है कि प्रभावित शिक्षकों के लिए एकमुश्त विशेष स्थितिलीकरण प्रदान किया जाए तथा टीईटी अथवा बी.एड. के अभाव में किसी भी शिक्षक की पदेनति, वेतनवृद्धि, क्रमोन्नति एवं अन्य सेवा लाभ प्रभावित न हों। साथ ही विभाग द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर शिक्षकों के अर्जित सेवा अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व अवैध शराब पर उठाए सवाल

हरिभूमि न्यूज़ ►► साजा

प्रदेश किसान मोर्चा के मीडिया सह-प्रभारी मूलचंद शर्मा ने साजा में आयोजित एक मीडिया संवाद के दौरान प्रदेश की प्र शा स नि क प्र ा र्य प्र ण ा ली , राजस्व विभाग की स्थिति और अवैध शराब कारोबार को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का समझौता

- स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी अब भी पुरानी रा ज नी ति क मानसिकता से प्रभावित होकर कार्य कर रहे हैं तथा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अनुचित व्यवहार कर रहे हैं। शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अब अधिकारी राज नहीं, बल्कि जनसेवा और जवाबदेही आधारित शासन व्यवस्था लागू है। यदि कोई अधिकारी राजनीतिक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर कार्य करता है या कार्यकर्ताओं का अपमान करता है, तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन का मूल दायित्व जनता की सेवा करना है, न कि किसी राजनीतिक विचारधारा के आधार पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाना।

कार्य कर रहे हैं तथा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अनुचित व्यवहार कर रहे हैं। शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अब अधिकारी राज नहीं, बल्कि जनसेवा और जवाबदेही आधारित शासन व्यवस्था लागू है। यदि कोई अधिकारी राजनीतिक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर कार्य करता है या कार्यकर्ताओं का अपमान करता है, तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन का मूल दायित्व जनता की सेवा करना है, न कि किसी राजनीतिक विचारधारा के आधार पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाना।

भाजपा कार्यकर्ताओं से दुर्लव्वहार पर जताई निषेधाज्ञा

उन्होंने दुर्ग जिले में सुशासन तिवार के दौरान एक अधिकारी द्वारा भाजपा कार्यकर्ता के साथ कथित दुर्व्यवहार की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार द्वारा की गई कार्रवाई स्वागतयोग्य है। शर्मा ने कहा कि किसी भी अधिकारी को जनप्रतिनिधियों अथवा राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ असम्मानजनक व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर राजनीतिक पूर्वाग्रह से कार्य करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

राजस्व विभाग में लंबित प्रकरणों और भ्रष्टाचार पर उठाए सवाल

राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को गंभीर धिता व्यक्त करते हुए शर्मा ने कहा कि प्रदेशभर में हजारों राजस्व प्रकरण वर्षों से लंबित पड़े हुए हैं, जिससे आम नागरिकों को लगातार तहसील कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग में भ्रष्टाचार और अवैध लेन-देन की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, जिससे शासन की छवि प्रभावित हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राजस्व मंत्री टंकराज वर्मा से मांग की कि लंबित प्रकरणों और भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए तथा दक्षी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

अवैध शराब कारोबार पर विशेष अभियान चलाने की मांग

मूलचंद शर्मा ने अवैध शराब बिक्री को भी गंभीर समस्या बताते हुए कहा कि कई क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन की जानकारी के बावजूद अवैध शराब का कारोबार जारी है। इससे युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है और सामाजिक वातावरण प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद प्रमावी कार्रवाई नहीं होना नित्ता का विषय है। शर्मा ने जिला पुलिस प्रशासन से मांग की कि अवैध शराब और मद्यक दवाओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। अपने बयान के अंत में उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप कानून व्यवस्था को मजबूत करना, प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही तय करना अनिवार्य है, ताकि जनता का विश्वास शासन और प्रशासन दोनों पर और अधिक मजबूत हो सके।